::प्रबंध सम्पादक::
विजय जैन

:: सम्पादक::
प्रो. वीएन पाल

::सम्पादक ब्युरो::
डॉ. आर्य बी. भारद्वाज
एमएस अम्बाड़ी
महेश पाण्डेय
अरुण कुमार बौद्ध
डॉ. स्वाती भटनागर
पीपी मिश्रा
सरदार हरनाम सिंह
रॉनिल दाइमारी
ज्ञान बहादुर थापा
रोहन देशमुख
तेजेन्द्र चौधरी
अजय सिंह किरार

:सम्पादक बोर्ड:
हरभजन सिंह जादौन
अजमर सिंह यादव
संतोष वर्मा
छविनाथ सिंह

:फोन:
09759561157
09761184199

:: मुद्रक ::
ओमियो प्रिंटर्स
लखनउ

: प्रकाशक:
पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल का मुखपत्र, २४६ वजीराबाद एक्सटेंसन, काली घाट मार्ग, दिल्ली-११००८४

पॉलिटिकल इंजीनियरिंग

अंक-तीन | ग्राम प्रधान मोर्चा | संस्करण- कानपुर मण्डल | दिसम्बर-2013

कन्नौज के लोग हनुमान हैं वोटर्स पार्टी है जामवंत

जीएनएस.। कोई बात सरकार से मनवाना हो तो सरकार को ज्ञापन देने का अब असर नही होता। सांसदों विधायकों को समझाने से भी अब कोई नतीजा नही निकलता। क्योंकि ये लोग अपनी पार्टी के मुखिया की हां में हां मिलाने के लिये कानूनन मजबूर हैं। पार्टी का मुखिया दिन को अगर रात कहे तो सांसदों-विधायकों को रात ही कहना पड़ता है। अगर ऐसा न करें तो वे सांसद-विधायक ही नही रह जायेंगे।

ऐसा कहना है जाने-माने राजनीति सुधारक श्री भरत गांधी का। श्री गांधी ने एक भेट वार्ता में कहा कि हमारे देश में व्हिप जैसे इस तरह के तमाम कानून हैं, जो सांसदों-विधायकों को जनता के प्रति वफादार होने की बजाय पार्टी के मुखिया के प्रति वफादार बना देते हैं। इसलिये अब लोगों को चाहिये कि वह अपनी बात मनवाने के लिये केवल पार्टियों के मुखिया को कहें। यदि वह न माने तो उसके चुनाव क्षेत्र में चुनाव के दिन उसे हराने का काम करें।

एक बार हार का मुंह देखते ही वह जनता की मांग मान लेगा।

राजनीति सुधारक श्री भरत गांधी

उन्होंने कहा कि वोटरों की देश में साझी सम्पत्ति है। किन्तु अमीरों के पैसे से राजनीति करने वाली दलाल पार्टियों के नेता लोग अंग्रेजों के जाने के बाद से अब तक ये बात जनता को बताये ही नहीं। उन्होंने कहा कि जब संसद में उनकी बात मानकर १३७ संसदों ने वोटरों की साझी सम्पत्ति को कानूनी मान्यता देने का प्रस्ताव संसद में पेश किया तो दलाल पार्टियों के मुखिया लोग एकजुट होकर रोक दिये। सभी सांसद उनका मुंह ताकते रह गये। इस शाजिस में गरीबों की पार्टी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया भी थे।

श्री गांधी ने कहा कि जब सांसदों-विधायकों को देश में कोई अधिकार ही नही है, तो उनके सामने फरियाद करने से क्या होगा? उन्होंने वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल की तारीफ करते हुये कहा कि यही एक मात्र पार्टी है जिसने देश की राजनीति को सुधारने व उसे पटरी पर लाने के लिये सांसदों-विधायकों की बजाय पार्टी अध्यक्षों को निशाने पर लिया है। इसीलिये पार्टी अमेठी, रायबरेली व कन्नौज में सघन काम कर रही है।

...शेष पृष्ठ तीन पर

प्रधान चुनें प्रधानमंत्री- हुक्मरानों के सामने प्रस्ताव पेश-महेश पाण्डेय

कन्नौज के ग्राम प्रधानों द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, कानून मंत्री कपिल सिब्बल, पंचायती राज मंत्री मणिशंकर अैय्र, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी एवं एनडीए चेयरपर्सन शरद यादव प्रेषित कर दिया गया है। सभी लोगों को श्री गांधी ने अंग्रेजी में पत्र लिखते हुये निवेदन किया है कि प्रधानों को प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार देने के लिये लिखित कार्यवाही करें व श्री गांधी के माध्यम से प्रधानगण को सूचित करें।

उक्त जानकारी राजनीति सुधारो अभियान के मण्डल संयोजक श्री महेश पाण्डेय ने दी है। श्री भरत गांधी ने 25 नवम्बर को सोनिया गांधी व शरद यादव को पत्र भेजते हुये निवेदन किया है कि दोनों लोग अपने-अपने गठबंधन की पार्टियों के मुखिया लोगों को प्रधानों का प्रस्ताव भेजते हुये प्रस्ताव स्वीकार करने का लिखित निवेदन करें व इस निवेदन की एक प्रति श्री गांधी को भेजते हुये उनके माध्यम से प्रधानगण को सूचित करें।

राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि वह प्रधानमंत्री को इस आशय का पत्र लिखें। 28 नवम्बर को प्रेषित पत्र में प्रधानमंत्री से कहा गया है कि वह कानून मंत्रालय को प्रधानों के प्रस्ताव पर संविधान संशोधन विधेयक बनाने के लिये पत्र लिखें व विदेश मंत्रालय को प्रधानों के प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय संधि का मसौदा बनाने के लिये पत्र लिखें। जिससे यूरोप की तरह भारत के पड़ोसी देशों का एक वतन बनाना संभव हो सके और इस वतन के प्रधानमंत्री का चुनाव इन देशों के ग्राम प्रधानों को देना संभव हो सके। ऐसा होने से हथियार खरीदने के नाम पर देश के लोगों की जिस गाढ़ी कमाई को अमरीका की हथियार कम्पनियों को भेजा जाता है वह खरबों रूपया अब गांवों में विकास के लिये पंहुचने लगेगा। केवल इस एक काम से कम से कम 25 लाख रूपया हर साल हर एक गांव के खाते में आने लगेगा। पड़ोसी से दुश्मनी खत्म तो हथियारों पर होने वाला खर्च भी खत्म।

यह पत्र राजनीति सुधारो अभियान की ओर से देश के हुक्मरानों के सम्मुख पेश किया गया है। पत्र की मूल प्रतियों को अंग्रेजी में अभियान की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। वेबसाइट का पता है- www.politicalreforms.org

प्रधान चुनें प्रधानमंत्री श्रृंखला.....

टीवी चैनलों के हो-हुल्लड़ में गांव वालों की चीख गुम

गतांक से जारी....

..... टीवी चैनलों के मालिकों ने मैट्रो शहरों को 'देश' और 'राष्ट्र' कहना शुरू कर दिया व मैट्रो शहरों के निवासियों को ही देशवासी व राष्ट्रवासी कहना शुरू कर दिया। टीवी चैनलों के हो-हुल्लड़ में गांव वालों की चीख गुम हो गई है।

5. यह निष्कर्ष भी सत्य है कि निजी पूंजी से संचालित टीवी चैनलों ने मीडिया का स्वभाव इतना बदल डाला है कि मीडिया अब लोकतंत्र की इमारत का स्तम्भ नही रह गया है, यह इस इमारत की छत पर पड़ा असहनीय बोझ बन गया है, जिसने इस इमारत के ढ़ांचे को ही विरूप कर दिया है। अब संसद में वह बहस नही होती, जिसे देश के लोग चाहते हैं। संसद में अब वह बहस होती है, जिसे टीवी चैनलों के मालिक चाहते हैं। टीवी चैनल चूंकि खरबपतियों के निर्देशन में चलते हैं, इसलिये कार्यपालिका व विधायिका के साथ ही साथ लोकतंत्र का यह स्तम्भ भी खरबपतियों का गुलाम हो चुका है। गांव वालों के दर्द का बीन लोकतंत्र के ये स्तम्भ सुन तो रहे हैं, किन्तु भैस की तरह पागुर कर रहे हैं और जो कुछ सुन रहे हैं, उसे लार की तरह नीचे गिरा दे रहे हैं। अब तो निजी पूंजी से निर्देशित मीडिया न्यायपालिका को भी अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। मीडिया केवल धनउगाही के लिये जिस केस का ट्रायल शुरू करता है, पुराने मामलों को जस का तस छोड़कर न्यायपालिका भी अब उसी मामले का "स्वतः संज्ञान" लेता है व ट्रायल शुरू कर देता है। न्यायपालिका कानून के खूंटे से बंधी है, खूंटा गाड़ने वाले, यानी कानून बनाने वाले सांसद लोग खरबपतियों के खूंटे से बंधे हैं। ऐसी स्थित में न्यायपालिका कर भी क्या सकती है! वह ज्यादा से ज्यादा पुलिस व सेना की ताकत से खरबपतियों की मर्जी से बने बनाये कानूनों की चहरदीवारी में जनता को कैद रखने भर का काम कर सकती है। (...शेष जनवरी, 2014 के पहले अंक में जारी)।

वोटरशिप लाओ गरीबी हटाओ.....

आर्थिक गुलामी व गरीबी में फर्क क्या है?

14 अगस्त 1947 की रात को ब्रिटेन की रानी ने कुर्सी के साथ-साथ देश की सारी सम्पत्ति का मालिकाना हक भी देश के सभी लोगों को दिया था। किन्तु सम्पत्ति पर 15 अगस्त के बाद भी वही लोग कब्जा जमाये रहे, जिन्होंने पहले से कब्जा किया हुआ था। यहां के नेताओं को कुर्सी मिल गई, किन्तु जनता को सम्पत्ति, या उसका किराया, मतलब कि वोटरशिप आज तक न मिली। भारत के लोगों को राजनीतिक आजादी मिल गई किन्तु आर्थिक आजादी नही मिली।

लोकतंत्र में गरीब नागरिकों की आर्थिक गुलामी का खात्मा गरीबों की मदद करने से नहीं, वोटरों की साझी सम्पत्ति पर से कब्जा हटवाने से होगा या इस सम्पत्ति का किराया वोटरों को हर महीना दिलाने से होगा। **वोटरों की सम्पत्ति का यह किराया ही वोटरशिप है। वोटरशिप के बगैर आर्थिक आजादी असंभव है। आर्थिक आजादी के बगैर गरीबी का खात्मा असंभव है। वोटरशिप रोटी में हिस्से जैसा है, काम से मिला पैसा भूसे जैसा।**

अधिकांश किसान जब ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, तो बैलों को कटवा देते हैं। उसी प्रकार चौतरफा मशीनें लगा लेने के बाद अब अमीरी रेखा के ऊपर के लोग गरीबों को फालतू जनसंख्या मानने लगे हैं। गरीबों के घरों में जानबूझकर मंहगाई पैदा करके व पैसे की तंगी पैदा करके उन्हें मारने में लगे हैं। विकास के पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय व योजना आयोग को इसी काम पर लगाया गया है। देश में हो रही आत्महत्यायें आर्थिक नरसंहार की इसी नीति का परिणाम है।

इस आर्थिक नरसंहार को रोकने के लिए 137 संसद सदस्यों ने सन् 2005 में संसद में वोटरशिप के नाम से एक प्रस्ताव पंश किया, किन्तु अरबपतियों ने पार्टियों के अध्यक्षों को धमका दिया। अध्यक्षों ने सांसदों को व्हिप कानून का डर दिखाया। सांसदों ने आगे बढ़ने की हिम्मत नही की। संसद में यह प्रस्ताव लटक गया। गरीबी, गुलामी व आत्महत्यायें जारी है। ऐसा ही चला तो देश अमीर होता जाएगा, फिर भी ये समस्यायें आगे हजारों साल तक बनी रहेंगी।

किसानों के पालतू बैल अपने मालिक से प्रेम करके ज्यादा अनाज पैदा करने लगेंगे, तब भी बैल को रोटी नहीं, भूसा ही मिलेगा। भूसा खाने के लिए विवश **बैल गरीब नहीं, गुलाम होते हैं।** बैलों की तरह ही देश के गरीब नागरिक भी गरीब नहीं, कष्टात्मक काम कराने के लिये अरबपतियों द्वारा पाले गये गुलाम हैं। उन्हें मंदबुद्धि, निकम्मा, पिछले जन्म का पापी, शराबी, जुआड़ी व आलसी कहना या तो अज्ञान है, या उनके खिलाफ शाजिस, या दोनों।

रोटी के लिए काम करने की शर्त लगाना व अरबों रूपये का वैभव-विलास विरासत जैसे कानूनों से फ्री में देना आर्थिक गुलामी का सुबूत है। गरीबी देश में पैसे की कमी के कारण नहीं होती, कानूनों के कारण होती है। गरीबी आर्थिक गुलामी वाले हरामखोरी रक्षक कानूनों का नतीजा है। आर्थिक गुलामी फोड़ा है, गरीबी इस फोड़े से बहने वाला मवाद। गरीबी उन्मूलन करने का मतलब होता है-मवाद की सफाई करना व फोड़े को बनाये रखना।

गरीबी व गुलामी में अंतर न समझने के कारण गत 60 सालों में गरीबों ने गरीबी पर भाषण देने वाले व अमीरों की राजनीति करने वालों को अपनी जाति व अपने क्षेत्र व अपने धर्म के नाम पर वोट दिया व कुर्सी पर बैठाया। जनता वोटरशिप पर जब तक वोट देना नहीं सीखेगी, तब तक गरीबी एक घर से दूसरे घर में कचरे की तरह हटती रहेगी लेकिन खत्म नहीं होगी (...शेष जनवरी, 2014 के पहले अंक

प्रस्ताव देने वाले ग्राम प्रधानों की सूची

कमलेश कुमार
राजकुमारी
रामपाल
सुरेश चंद
रामपाल सिंह पाल
राम सिंह
शशिकान्त शुक्ला
पुत्तन सिंह
हरि शंकर सैनी
लालता प्रसाद मिश्रा
राम बेटी कठेरिया
योगेन्द्र कुमार
गंगाराम
प्रताप सिंह यादव
प्रभा देवी
आशा यादव
सुरेश चंद
हरभजन सिंह
निर्मला देवी
शबनम बानो
शांति देवी
प्रेम चंद्र वर्मा
सुभाष चंद्र
चंद्रावती
राजेन्द्र यादव
कृष्णवती यादव
शारदा देवी
मुन्नादेवी
विद्या देवी
राम सिंह
सुमन देवी
रामचंद्र
रामविलास
सबने अली
मुन्नी देवी
राम दास कुशवाहा
सुमन देवी
सुरेनद्र सिंह यादव
सीताराम कुशवाहा
संताष कुमार
इसरार अली
रघुवीर सिंह
अशोक दुबे
राम रतन राजपूत
राधाा कृष्ण
देवसरन जी
इन्द्रपाल सिंह
मनोज कुमार

प्रधानों व पूर्व प्रधानों से अपील

१. ग्राम प्रधान मार्चा जो ज्ञापन तैयार करके सम्मेलन के निमंत्रण पत्र के साथ भेजा गया था, उसे भरके कृपया शासन को भेज दें व उसकी एक छाया प्रति मोर्चा के कार्यालय तक पंहुचवा दें। यदि शासन को भेजने में कोई असुविधा महसूस करें, तो मोर्चा के कार्यालय तक पंहुचवा दें।

२. राजनीति सुधारो अभियान की १५ सदस्यीय संघर्ष कमेटियों का गठन करके या तो वह सूची मोर्चा के कार्यालय तक पंहुचवा दें या तो फोन पर लिखवा दें। इन लोगों को २५ से २८ दिसम्बर को होने वाले तिर्वा के प्रशिक्षण शिविर में पंहुचाने का इंतजाम करे। भोजन व रहने का प्रबंध करने के लिये इस शिविर में आने वालों से ३०० रूपया फीस लिया जायेगा। पहले तो यह फीस उनको मंहगी लगेगी, किन्तु चार दिन की ट्रेनिंग लेकर लौटेंगे तो उन्हें लगेगा, जैसे उन्होंने ३०० रू. में तीन लाख का फायदा पा लिया हो।

३. फोन से समय लेकर अभियान के वक्ताओं को बुलायें व अपने गांव के लोगों के बीच उनकी मीटिंग करवायें। जिससे ग्रामवासी भी गांवों के अधिकार बढ़ाने में ग्राम प्रधानों का साथ दे सकें।

४. तिर्वा के ग्राम प्रधान सम्मेलन में श्री भरत गांधी का पूरा वक्तव्य सुनने के लिये कृपया अभियान की वेबसाइट www.politicalreforms.org के ऑडियों पेंज पर जाकर लॉग ऑन करें- मोबाइल की दुकान में जाकर आप श्री गांधी के पूरे प्रवचन को अपने मोबाइल में डलवा भी सकते हैं व जब चाहें किसी को भी सुनाकर उसको भी अभियान के साथ हमसफर बना सकते हैं।

५. यदि कोई अधिकारी आपको प्रताड़ित कर रहा है तो उसकी बातें रिकार्ड करके उसके खिलाफ याचिका दायर करें। याचिका दायर करने में अभियान का अधिवक्ता प्रकोष्ठ आपकी मदद करेगा।

कैसे सुधरे राजनीति...

समस्याओं का नकली समाधान पेश करने वाले लोग समाज के लिए स्वयं एक समस्या हैं। - ऐसा मानना है। श्री भरत गांधी जी का। श्री गांधी देश के जाने माने राजनीति सुधारक है।

उन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिख कर हमारा मार्गदर्शन किया है। श्री गांधी २३ साल की उम्र में ही इंसान को सुखी बनाने का रास्ता खोजने के लिये निकल पड़े थे। अपने २० साल लम्बी इस खोजी यात्रा में उन्होंने इंसान की लगभग हर समस्या का मार्ग निकाल लिया। राजनीति कैसे सुधारें, समाज कैसे सुधारें, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारें, अर्थव्यवस्था कैसे सुधारें, राजव्यवस्था कैसे सुधारें.... आदि सभी विषयों पर श्री भरत गांधी ने अनोखा रास्ता निकाला है। ऐसे रास्ते जिन्हें न तो दुनिया ने कभी सोचा, न सुना और न देखा। गरीबी और गुलामी कैसे खत्म हो; इस विषय में श्री भरत गांधी की किताबें, सीडी व डीवीडी पहले से उपल्बध हैं। आज हम आपकी मुलाकात करायेंगे श्री भरत गांधी से और पूंछेंगे उनसे केवल उन सवालों को जिनसे आज की गंदी राजनीति को सुधारा जा सके। -संपादक (पिछले अंक से जारी....)।

सवाल-8: .....**अधिकारियों का दोष क्या है?**

भरत गांधी - अधिकारी वर्ग देश के अरबपतियों और उनके पाले हुए दलाल नेताओं को भ्रष्टाचार करने का गुण सिखाता है, यही उसका दोष है। ऐसे करने की प्रेरणा उसे उत्तराधिकार कानून से मिलती है। कानूनों की पढ़ाई करने के कारण वह समझ जाता है कि देश लोकतंत्र के उसूलों पर नहीं चल रहा है बल्कि अरबपतियों के चाबुक से चल रहा है। वह समझ जाता है कि अरबपतियों की ताकत है उत्तराधिकार कानून। इसी कानून के सहारे उनके बच्चे बिना किसी काबिलियत के अरबपति बन जाते हैं और चंदा देकर सभी पार्टियों के अध्यक्षों को अपनी कठपुतली बना लेते हैं। साधारण लोग यह समझते हैं कि देश को नेता और अधिकारी चला रहे हैं। बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि नेताओं को अरबपति लोग चलाते हैं और अधिकारियों को नेता लोग। यह देखकर शासक बनने का हर अधिकारी का सपना टूट जाता है और वह देश चलाने वाली सबसे बड़ी सत्ता यानी अरबपति बनने में लग जाता है।

सवाल-९: यह बात समझ में नहीं आयी कि उत्तराधिकार कानून अधिकारियों को भ्रष्ट कैसे बनाता है?

भरत गांधी - अधिकारी यह जान जाता है कि इमानदारी से काम करने पर भी वह अपना पद अपने बच्चों को उत्तराधिकार में नहीं दे सकता। किन्तु अगर वह अधिक से अधिक सम्पत्ति जमा करने में कामयाब हो जाए तो सम्पत्ति को अपनी अगली पीढ़ी को उत्तराधिकार कानून के द्वारा दे सकता है। इसीलिए वह काम पर कम ध्यान देता है और पैसा बटोरने पर ज्यादा। अधिकारी ही मंत्रियों का सलाहकार होता है। वह मंत्रियों को समझाता है कि इमानदार मंत्री होने से आपका पद आपके बच्चों को नहीं मिलेगा, उन्हें चुनाव के अखाड़े में कुश्ती लड़नी पड़ेगी। इसलिए अच्छा यही है कि काम पर कम ध्यान दीजिए और पैसे पर ज्यादा। वह समझाता है कि इमानदार रहकर के भी एम0 पी0 और एम0 एल0 ए0 का पद उत्तराधिकार में बच्चे को नहीं दिया जा सकता लेकिन बेईमान होकर जमा की गई सम्पत्ति को बच्चे को दिया जा सकता है। यह बात मंत्री को तो समझ में आती ही है साथ ही साथ सांसदों व विधायकों को भी बड़ी आसानी से समझ में आती है। और अंत में जो अधिकारी और जो नेता भ्रष्ट नहीं होता उसकी गिनती बेवकूफों में शुरू हो जाती है।

१० तो क्या आप यह कहना चाहते है कि उत्तराधिकार कानून खत्म किये बिना भ्रष्टाचार रोकना संभव नहीं है?

भरत गांधी - अगर संभव होता तो भ्रष्टाचार अब तक खत्म हो चुका होता। लेकिन उत्तराधिकार कानून से सरकार जो रकम बच्चों को फ्री में देती है, वह रकम कम कर दी जाये तो भ्रष्टाचार कम हो जायेगा, बड़ी कर दी जाये तो भ्रष्टाचार बड़ा हो जाएगा और अगर यह रकम बेलगाम कर दिया जाये तो भ्रष्टाचार भी बेलगाम हो जाता है। इसलिए उत्तराधिकार कानून से फ्री में मिलने वाली रकम की केवल सीमा भी तय कर दी जाये तो बड़े भ्रष्टाचारियों का सफाया हो जाएगा। उस सीमा से ज्यादा पैसा कोई जमा ही नहीं करेगा। उत्तराधिकार की सीमा बनने पर सीमा से ज्यादा दौलत न तो अरबपति जमा कर पाएंगे, न नेता जमा कर पाएंगे और न तो अधिकारी ही। राजनीति की गाड़ी चलाने वाले चालक दल के ये तीन वर्ग अगर भ्रष्टाचार करना छोड़ देंगे तो राजनीति लोकतंत्र की पटरी पर दौड़ सकती है। और राजनीति का चरित्र ऊंचाई हासिल कर सकता है।

११ राजनीति को गंदी करने में बुद्धिजीवियों का हाथ किस प्रकार है?

शेष जनवरी-2014 के अंक में जारी.....

कन्नौज के लोग हनुमान हैं वोटर्स पार्टी है जामवंत ...

श्री गांधी ने कहा कि हनुमान जी को अपनी ताकत भूल जाने की आदत थी। इसलिये जामवंत को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ती थी। इसी प्रकार वीपीआई एक ऐसी पार्टी के रूप में सामने आई है, जो कन्नौज लोकसभा के लोगों को याद दिला रही है कि चुनाव में समाजवादी पार्टी को हराके वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल को कन्नौज के लोग जिता सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो पूरा देश कन्नौज की ओर देखेगा और पूरे देश में वीपीआई के प्रत्यासी ही जीतने लगेंगे। राजनीति के कैंसर व एड्स की दवा को वोटर्स पार्टी ने खोज लिया है किन्तु पैसे वाले लोग इस असली दवा के प्रचार को रोक कर अखबारों व टीवी चैनलों से नकली दवाइयों का प्रचार कर रहे हैं। वीपीआई को कन्नौज से जीत मिलते ही पूरे देश के लोगों के रोम-रोम कन्नौज के इस एहसान के लिये उनको दुआएं देगे और कन्नौज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जायेगा।

वोटर्स पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पर लेकर बड़ी पार्टियों के मुखिया लोगों के चुनाव क्षेत्रों में उनको हराने के लिये काम कर रहे हैं। इसलिये इन क्षेत्रों की जनता का फर्ज बनता है कि अपनी-अपनी पार्टी के मुखिया से पूंछें कि आखिर वे लोग वोटर्स पार्टी के मुद्दों को क्यों नहीं मान रहे हैं? बहस के लिये तैयार क्यों नही है? अगर अआपका सांसद पूंछने के लिये आमने-सामने न मिलें, तो उसको चुनाव में चुपके से हरा दें। फिर तो उनके सामने दो ही रास्ते बचेंगे। पहला यह कि जनता से दुबारा वोट लेने के लिये वोटर्स पार्टी के मुद्दे मान लें और दूसरा यह कि राजनीति के अखाड़े से बाहर हो जायें।

क्यों करें मोदी पर विश्वास?

गतांक से जारी....

बिकाऊ टीवी चैनलों व अखबारों के मालिकों ने अपना-अपना लाउडस्पीकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी व दिल्ली में अन्ना हजारे के एक विश्वासघाती चेले को किराये पर उठा दिया है। कह रहे है कि मोदी को वोट दो। वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल मोदी के सामने कुछ सवाल उठा रही है, मोदी जवाब देने की हिम्मत करें तो स्वयं वीपीआई भी मोदी का साथ दे सकती है। लोकसभा चुनाव तक सवालों की यह श्रृंखला चलती रहेगी। जो भी मोदी का साथ देने की बात करे, उससे भी वोटर्स पार्टी सवाल करती है। मोदी के प्रचारको से विनम्र निवेदन है कि एक नये धोखे का शिकार बनने व जनता को बनाने से पहले ठहर कर सोचें- संपादक।

सवाल-पांच: सभी पार्टियां देश के विकास के नाम पर गरीबों की रोटी छीनती हैं, व चंदा देने वाले खरबपतियों का विकास करती हैं। मोदी ने भी गुजरात में यही किया। देश के गरीबों व गुलामों के साथ जब पिछड़ी जातियों के नेता ही न्याय नहीं किये। तो मोदी जैसा आदमी न्याय कैसे करेगा?

सवाल-छह: गत 16 साल से कन्नौज की जनता के सिर पर सवार श्री मुलायम सिंह जी को चुनाव में हराने के लिये वोटर्स पार्टी, भाजपा व बसपा का साझा प्रत्याशी खड़ा करके सपा को कन्नौज से हराने की बात पर मोदी राजी क्यों नहीं हैं?

सवाल-सात: खरबपतियों के पालतू नेता गरीबों के मोहल्ले में कभी ''जनता'' बनके कभी ''राष्ट्रभक्त'' बनके कभी ''आम आदमी'' बनके उसी तरह जाते रहे हैं। जैसे भेड़िया रात में बकरियों के पास अपनत्व दिखाने आता है व घड़ियाली आंसू बहाता है। मोदी क्या करेंगे? यह नही बता रहे हैं। केवल ठगों की तरह यह कह रहे हैं कि ''मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। सब ठीक हो जायेगा''। इतिहास गवाह है कि टीवी चैनलों व अखबारों के मालिकों ने जिसे भी हीरो बनाया, सभी ने जनता को ठगा। फिर मोदी पर भरोसा कैसे करें? (...शेष जनवरी, 2014 के पहले अंक में जारी)।

किस समाज की नेता हैं मायावती

मायावती को दलित की बेटी के नाम पर दलितों ने अरबपती बना दिया और खुद मजदूर ही बने रह गये। मायावती कुर्सी पायीं तो सवर्णों की तरह अपने समाज के भूगोल की चिंता न करके अपने इतिहास की चिंता किया। आज अपनी जाति के इस दलित सामंत को देखकर झुग्गी-झोपड़ियों की दुर्गंध व आर्थिक गुलामी की घुटन में जी रहा दलित समाज मायावती से ठगा महसूस कर रहा है। मायावती फिर दलित की बेटी के नाम पर वोट मांगने चुनावी रैली कर रहीं हैं। वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल पेश करती हैं मायावती से कुछ सवालों की श्रृंखला।

सवाल (तीन)- तथाकथित बड़ी जातियो के सामंती लोग वोटरों को हर महीने वोटरशिप की रकम देने का विरोध करें तो बात समझ में आती है लेकिन मायावती क्यों करती हैं? कुछ दलित नेता कहते हैं कि हर दलित परिवार को सरकार हर महीने १७५०० रूपया देने लगेगी तो उनका मन बढ़ जायेगा। बड़ी जातियों के बच्चें की तरह वे भी कुर्ता पहन कर नेता बन जायेंगे। फिर दलितों में भी तमाम नेता पैदा हो जायेंगे। वे कहते हैं कि दलित जाति के लोग तभी तक एक नेता की छतरी में गोलबंद रहेंगे जब तक कि वे गरीब, अशिक्षित व पिछड़े बने रहते हैं। वोटरशिप कानून बनते ही हर दलित के परिवार में १७५०० रूपया आने लगेगा। फिर न तो वे गरीब रह जायेंगे, न तो अशिक्षित व पिछड़े ही रह जायेंगे। फिर दलित एक झंडे के नीचे गोलबंद भी नही रहेंगे। वे कहते हैं कि इसलिये वोटरशिप का कानून नहीं बनना चाहिये। मायावती शुरू से ही मुलायम सिंह की तरह वोटरशिप के कानून का विरोध कर रही हैं। इस कानून का ९० प्रतिशत लाभ गरीब दलित समाज का ही है। जब मायावती वोटरशिप कानून का विरोध कर रही हैं तो मानना ही पड़ेगा कि मायावती अपने सुख के लिये दलित समाज को सुखी नहीं देखना चाहती। आखिर जब दलितों का सुख मायावती से देखा नही जाता, तो क्यों दें मायवती को वोट?

राजनीति सुधारकों की अगली ट्रेनिंग २५ दिसम्बर को तिर्वा में

राजनीति सुधारो अभियान की आगामी प्रशिक्षण शिविर इसी तरह का प्रशिक्षण शिविर २५ से २८ दिसम्बर के बीच कन्नौज के तिर्वा टाउन में भी आयेजित है। दोनो ही शिविरों में श्री भरत गांधी राजनीति सुधारने के लिये काम करने के इच्छुक विद्वानों को प्रशिक्षित करेंगे। तिर्वा के शिविर में भाग लेने की फीस रू. ३०० निर्धारित है। कोई भी जो शिविर में शामिल होना चाहता है, फोन नम्बर-09198416666 पर फोन करके अपना नाम लिखवा सकता है, फीस मौके पर ही जमा करनी होगी।

प्रस्ताव देने वाले ग्राम प्रधानों की सूची

अनिल कुमार कन्नौजिया
संजीव कुमार
राम आसरे जी
रियाजुल खान
ओंकार गुप्ता
योगेनद्र कुमार यादव
राम मूर्ति
राम भरोसे
आशा
महबूब आलम
बादाम सिंह
किरण
जसोदा
राजेंद्र कुमार
बृज किशोर तिवारी
इंद्र पाल
जगमोहन सिंह
राज कुमार
दया राम सागर
राम वीर
एहसान मोहम्मद
सीमा देवी
पप्पी
कमल किशोर राजपूत
संतोष कुमार वर्मा
विनीता देवी